



जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION



JAL CHARCHA

जल चर्चा

2020

October

save
water



भारत सरकार
Government of India

कोरोना से बचें



हाथ धोएं बार बार



सही से मास्क पहनें



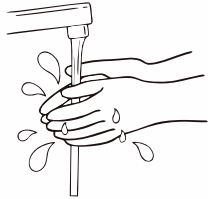
निभाएं दो गज की दूरी



जब तक दवाई नहीं
तब तक ढिलाई नहीं

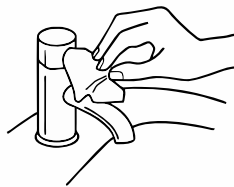
THE RIGHT WAY TO HANDWASH

1



Wet your hands

2



Turn off the tap

3



Apply soap

4



Rub your hands
for 20 seconds

5



Turn on the tap
and rinse well

6



Pat dry

SAVE WATER TO MAINTAIN HYGIENE

CONTENTS

• From the Chief Editor's Desk	2
• हेलिकल वाव गुजरात	3
• पश्चिम बनास नदी	4
• Conservation	5
• River Rejuvenation	6
• PMKSY	7
• जल योद्धा	8
• पानम बाँध	9
• Namami Gange	10-13
• Campaign	14-16
• Know Zone	17
• 17 th Water Talk	18
• People's Initiative	19
• News In Brief	20-23
• Snippets	24
• जन की बात	25
• NGO	26
• In Newspaper	27
• Institute	28



3 हेलिकल वाव गुजरात



4 पश्चिम बनास नदी



5 Conservation



6 River Rejuvenation



9 पानम बाँध



10-13 Namami Gange



26 NGO



28 INSTITUTE

Chief Editor : U.P. Singh

Editor : Sanjay Awasthi

Co-Editor : Girraj Goyal

Sub - Editor : Mohit Sharma

Design & Comm. Team : Fusion
Corporate
Solutions Pvt. Ltd.

Publisher : B.H.T. Vaiphei

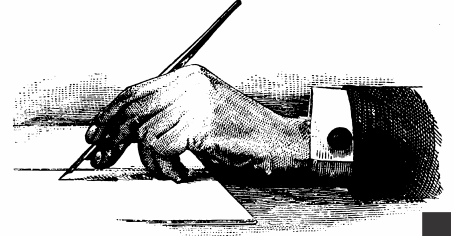
[as Under Secretary (IEC), Ministry of Jal Shakti, Do
WR, RD & GR
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001]
Printer : Krishna Enterprises
2070/S, Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi - 110055

Reproduction in any form is prohibited without written permission.
Any dispute related to the content of the magazine should be addressed
to the publisher.

“



मुख्य संपादक की कलम से



”

हमारा देश जल की उपलब्धता के लिए मानसून पर निर्भर है। इस वर्ष एक अच्छे मानसून की समाप्ति के बाद से हमारे मुख्य बांध व जल स्रोत पानी से लबालब हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 123 बड़े बांधों में लगभग 139.158 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 104% है। अब हमारा यह दायित्व है कि हम इस जल को संभलकर व मितव्ययता के साथ खर्च करें, जिससे कि गर्मी तक हमें पानी की कमी ना हो। इसी के साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आने वाले त्योहारों के मौसम में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरतें। इसी को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने व हाथों को स्वच्छ रखने के महत्व को दर्शाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि "जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं"।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सितंबर का महीना हमारे विभाग के लिए केवल इसलिए विशेष नहीं था कि 27 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया बल्कि यह महीना इसलिए भी विशेष था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत बिहार और उत्तराखंड में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड में पिछले 6 वर्षों में सीवेज शोधन क्षमता 4 गुना बढ़ी है। बिहार में दो एसटीपी परियोजनाओं का उद्घाटन भी पटना शहर में गंगा नदी को गंदे पानी से मुक्त करने की दिशा में 'मील के पत्थर' के समान है। हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत जगजीतपुर, हरिद्वार में 68 एमएलडी एसटीपी परियोजना का पूरा होना भारत में सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक सफल शुरुआत है। इन परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले प्रशंसा के शब्द हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं।

मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि 'कैच द रेन' अभियान के अंतर्गत आयोजित साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला में जिलाधिकारियों व नगर निगम आयुक्तों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जल शक्ति अभियान की शुरुआत के बाद से ही अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इससे हमें भी जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर किए जा रहे अनूठे उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इस श्रृंखला की खास बात यह है कि यह जल संरक्षण के विषय में सीखने का मंच बन गया है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए और भी खुशी हो रही है कि सितम्बर माह में नेशनल वाटर मिशन ने 17वीं 'वॉटर टॉक' का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जिसमें श्री एस.विश्वनाथ मुख्य प्रवक्ता थे। इस ई-वॉटर टॉक का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया पर किया गया और हजारों लोगों ने अपने घरों से ही इस संवाद में भाग लिया।

जल चर्चा के इस अंक में हम आपके साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मणिपुर में डोलेथाबी परियोजना के बारे में बता रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के पूर्वोत्तरी भाग में 7.54 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पैदा हुई है। जल चर्चा के इस भाग में हम मध्य प्रदेश की गेहलाना ग्राम पंचायत की सफलता की कहानी लेकर आए हैं, जहां मनरेगा और पीएमकेएसवाई के तहत स्टॉप डैम के निर्माण से ग्रामीणों की पानी संबंधित समस्या खत्म हो गई। मुझे यह बताते हुए भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 99 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी जिसमें से लगभग 50 पूरी हो चुकी हैं, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इनमें से कुछ परियोजनाएं कई वर्षों से लंबित थी जो कि अब पूरी हो रही हैं।

जल चर्चा के इस संस्करण में हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश के मावइयां गांव की कल्याणी नदी के छोटे से भाग के कायाकल्प की कहानी भी शामिल की है। यह उस नदी के छोटे से भाग की एक कहानी ही नहीं है बल्कि इस तथ्य का प्रमाण है कि किस प्रकार छोटे-छोटे कदम बड़े परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप जल चर्चा के इस अंक को सानंद पढ़ेंगे और अपने अमूल्य सुझाव के माध्यम से हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे।

शुभेच्छाओं सहित

(उपेंद्र प्रसाद सिंह)

हेलिकल, वाव गुजरात

जल चर्चा के इस अंक में हम आपको एक ऐसी बावड़ी से परिचित कराएंगे जो देश के उस राज्य में स्थित है जिसने सभी को 'बावड़ी परंपरा' से अवगत कराया। जी हाँ, हम आपको इस अंक में गुजरात स्थित एक बावड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप ने 'चंपानेर' शहर का नाम तो सुना ही होगा। यह शहर पूर्वी गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। आपको यह जानकारी आश्चर्य होगा कि चंपानेर देश के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखने वाले शहरों की श्रेणी में शामिल है। यहीं पर स्थित है, 'चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क' जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इस शहर में किले, मंदिर एवं मस्जिद समेत घूमने लायक कई जगह हैं जिसमें से एक है 'हेलिकल वाव'। इसे स्फेरिकल वाव के नाम से भी जाना जाता है।

ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। हेलिकल वाव चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है और यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। यह पहली नज़र में एक कुआँ होने का भ्रम दे सकती है क्योंकि इसका स्वरूप वाकई कुँए से मिलता जुलता ही है परन्तु इसमें नीचे उतरने के लिए कुंडलित सीढ़ियाँ (स्पाइरल के जैसी दिखने वाली सीढ़ियाँ) बनी हुई हैं। प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर है। इसका यह रूप एवं आकार ही इसे देश की अन्य बावड़ियों से भिन्न बनाता है। इसकी खासियत ही यह है कि यह अन्य बावड़ियों की तरह चौकोर न होकर गोल है। बावड़ी में सबसे ऊपर से ही एक तरफ से इसकी सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और इन सीढ़ियों की सहायता से पानी के सबसे निचले तल तक पहुंचा जा सकता है।

वैसे तो आप यहां साल भर कभी भी और किसी भी दिन घूमने जा सकते हैं लेकिन मानसून का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा बताया जाता है। मानसून के समय एक तो इस बावड़ी का जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं इस समय आप यहां की हरियाली का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ इस बावड़ी के अलावा कई बड़े - बड़े तालाब और कुँए भी हैं जिसे देखकर पता लगता है कि चंपानेर का जल प्रबंधन उच्च कोटि का एवं अपने समय से कहीं आगे का था। आप यदि घूमने के शौकीन हैं और ऐतिहासिक इमारतें आपको आकर्षित करती हैं तो चंपानेर अवश्य जाना चाहिए और साथ ही साथ हेलिकल वाव देखकर खुद को अपने देश के जल समृद्ध इतिहास से रूबरू कराना चाहिए।

आज मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में नई - नई ऊँचाईयों को छू रहा है लेकिन एक पहलु जिसे वह छोड़ता ही जा रहा है वह है पर्यावरण और प्रकृति। आज की तकनीक से लेस सभ्यता ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य हर घर तक पानी पहुंचाना सीख गया है लेकिन उस पानी को संरक्षित करना नहीं सीख पाया है। इस धरती के प्रत्येक मानव को यह समझने की आवश्यकता है कि जब जल खत्म हो जाएगा तब घरों के नल भी निरर्थक ही होंगे। यदि आधुनिक मनुष्य ने जल की अहमियत समझी होती तो शायद इस गंभीर जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे पूर्वजों ने जल के महत्व को समझा था और इसलिए धरती के जल का दोहन करने की जगह वर्षा जल संचयन का रास्ता चुना। जिसका परिणाम आज चंपानेर हेलिकल वाव जैसी सुन्दर और अद्भुत बावड़ियों के रूप में हमारे सामने हैं।

पश्चिम बनास नदी

बनास नदी का उद्गम राजस्थान के सिरोही जिले के नया सानवाड़ा/सानवारा गांव के निकट दक्षिणी अरावली पहाड़ियों से होता है। यह पश्चिम में माउंट आबू और पूर्व में अरावली की पहाड़ियों के बीच घाटी में से होकर दक्षिण की ओर बहती है। पश्चिमी बनास नदी गुजरात के बनासकांठा जिले से प्रवेश कर गुजरात राज्य के मैदानी इलाकों से होती हुई दक्षिण की ओर बहते हुए कच्छ के लिटिल रन के wetland में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 266 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 50 किलोमीटर भाग राजस्थान में तथा शेष भाग गुजरात में है। यह नदी गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों से होकर बहती है। बनास नदी को मौसमी प्रकृति की नदी माना जाता है, और यह सिरोही, माउंट आबू, बनासकांठा और पाटन जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने बेसिन के क्षेत्र में कई तालाबों को भरने के लिए भी यह नदी उपयोग में आती है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दीसा या डीसा, पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर स्थित है।

विभिन्न सहायक नदियाँ— सिपू बनास की एकमात्र दाहिनी सहायक नदी है, जो मुख्य नदी से मिलती है। बनास नदी के बाएं किनारे पर 6 सहायक नदियाँ बटरिया, सुकली, सेवरन, सुकेत, बालाराम और खारी हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं।

बनास नदी पर स्थित परियोजनाएं— स्वरूपगंज बांध, दांतीवाड़ा बांध, सिपू बांध, जिसमें दांतीवाड़ा बांध सबसे महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा दांतीवाड़ा बांध के लिए जल की आवक (inflow) का पूर्वानुमान दिया जाता है। साथ ही आबू रोड स्थल के लिए जल स्तर (Level Forecast) का पूर्वानुमान भी किया जाता है।



A Stop Dam to address MP Village's Water Woes under MGNREGA and PMKSY

Due to low rainfall every year, the Gehlana Gram Panchayat of Mandsaur district in Madhya Pradesh exhausted its groundwater resource for agriculture and livestock rearing. The waters of Shivna River, a small tributary of Chambal, flowing near the Gram Panchayat also could not help villagers in fulfilling their water needs due to excessive run-offs. The large tracts of land owned by farmers became barren due to scarcity of water putting the local population under extreme stress. The farmers raised the concern before the Gram Sabha. Consequently, a decision was taken to construct a stop dam on River Shivna not only to divert its waters to the fields but also to recharge the groundwater.

The construction of the stop dam with a 55 meter long sidewall was completed in 2016-17 to stop excessive run-offs. The dam has the capacity to store approximately 300 TCM. The total cost of the project was Rs. 27 lakh. While a sum of Rs. 6 lakhs was incurred under MGNREGA, the remaining funds were provided under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY).

After the completion of the project, the overall water availability has increased in the region. The groundwater table has risen by 2 feet and 80 hectares of land belonging to more than 50 farmers is benefitted through this work. The increased groundwater recharge and better irrigation facility have resulted in higher crop productivity. In addition, multiple varieties of commercial crops are now being cultivated which has ensured higher income for the farmers. Crop production has increased by 20-30% after the construction of the stop dam.

Shri Badri Lal, one of the beneficiary farmers of the project said: "Despite living in a locality blessed with a river, we did not have drinking water after January, every year. The local canals used to dry up post-monsoon due to which we were compelled to purchase water. After construction of this stop dam, we have water throughout the year. Now, we have doubled our agricultural production and live in much better conditions".



Locals Restore Small Stretch of Kalyani River in UP During Lockdown, IAS Officer Leads the Way

Small steps make big changes! This stands true in the case of an initiative taken up by an IAS officer to restore a small stretch of River Kalyani in Uttar Pradesh during the lockdown period.

Mindful of the fact that several people had lost their jobs and were returning to their villages in search of livelihood, District Magistrate, Barabanki, Dr. Adarsh Singh decided to employ the migrating people under MGNREGA to rejuvenate a 2.6 kilometer stretch of River Kalyani in Mawaiyan village. The local people had been demanding the restoration of the river for the past 30 years. The condition had become so bad that it was difficult to determine the actual course of the river. The district administration had been planning to start the work since September 2019 but due to lack of manpower could not go ahead. The unprecedented situation created due to the Covid-19 lockdown presented the district administration with an opportunity to serve twin purposes of river rejuvenation and employment generation.

With the help of the state government, the migrants were mapped and about 800 of them who had lost their jobs or whose livelihoods had been affected due to the global pandemic were employed under the project that costed Rs. 59 lakh. After the successful completion of the river revival work of 2.6 km stretch in Mawaiyan, the work was extended

to another 1.5 km stretch in the neighboring village, Haidargarh.

Led by Dr. Adarsh Singh Deputy Commissioner, MNREGA-Barabanki, Shri ND Dwivedi and Block Development Officer, Shri Hemanth Kumar Yadav adopted measures such as sensitizing villagers, eliminating encroachments, reducing garbage dumping and open defecation on the river bank. What made this project special was the excitement with which the workers did their job as it came as a ray of hope for several villagers who were struggling. And a sense that a revived river would ultimately benefit them added more commitment to their work.

As part of the river revival, first, all encroachments close to the river were removed followed by a stringent sensitization drive against open defecation and dumping garbage in the river. Thereafter, the daily wage earners removed the silt, dug the river 1.5 metre deep, and widened it by 25 metres to capture and store rainwater. They also repaired the catchment area. In about two months, the 2.6 km stretch was brought back to life followed by 1.5 km stretch in Haidargarh.

After the success of the first phase, the district administration is now planning to replicate the model to other villages in the vicinity as well to rejuvenate more stretches of 170-kilometres long Kalyani River.



Dolaithabi Project in Manipur Completed under PMKSY, Creates 7.54 thousand hectare Irrigation Potential



It is the success of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) that out of 99 prioritized projects nearly 50 have already been completed, a big achievement to provide farmers with adequate supply of water for agriculture in various parts of the country. One of the completed projects includes Dolaithabi Project in Imphal East district of Manipur, which was inaugurated in 2019 by Prime Minister Shri Narendra Modi.

The project was included in Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) of the central government in 2002-03 but due to unavailability of funds could not

progress. Besides, the project being in the difficult terrains of north-eastern region with adverse weather condition faced many hurdles like scarcity of resources, difficulty in transportation, reduced working period owing to frequent rains etc. Ultimately, this project saw the light of completion after being included in the 99 prioritized projects under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.

The project consists of a barrage which is 78.75 meter-long with 6 bays of 10 m each across Iril River and a canal system comprising one 2.58 km-long common canal that bifurcates into Left Main Canal (LMC) and Right Main Canal (RMC). The LMC is 17.30 km long including 2.58 km common carrier and RMC is 17.30 km long. Both canals together constitute 5500 hectares of Culturable Command Area. The project brought benefit to the tribal areas of Imphal & Senapati districts of Manipur which gave a boost to the agricultural activities in the area.

The project which has been completed in all aspects under PMKSY-AIBP has led to the creation of ultimate irrigation potential of 7.54 thousand hectares benefitting 15 villages on the Left Bank and 12 villages on the Right Bank. The total cost of the project work was Rs. 455.55 crore excluding the cost of establishment, out of which total central assistance was Rs. 305.4 crore.



Upstream of Dolaithabi project



Arial view of Dolaithabi barrage, Manipur



हाजी सरदार मोहम्मद

देश के सबसे सुन्दर शहरों में से एक - उदयपुर, अपनी झीलों के कारण जाना जाता है। इसे 'झीलों की नगरी' भी कहा जाता है। यहाँ की इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक देश - विदेश से आते हैं। इस शहर में इतनी सारी झीलें हैं कि यहाँ के निवासी भी झीलों की कुल संख्या बताने के नाम पर सोच में पड़ जाते हैं। गिरवा पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर चारों तरफ से वन, झील और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती अतुलनीय है पर क्या आपने कभी सोचा है की 'झीलों की



नगरी' की झीलों की वास्तविक छवि क्या है? यह दुखद है कि ये झीलें स्थानीय निवासियों के लिए कचरा फेंकने की एक जगह बन कर रह गयी थी। कचरा और जंगली पौधे इन झीलों की खूबसूरती को कम करने लगे थे परन्तु ऐसे में एक व्यक्ति है जो बीते 15 सालों से इन झीलों की साफ सफाई हेतु काम कर रहा है।

जल चर्चा के प्रत्येक अंक की ही तरह इस अंक में भी हम आपको ऐसे जल योद्धा से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने अपने परिश्रम से झीलों की छवि को परिवर्तित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर शहर के रहने वाले 74 वर्षीय हाजी सरदार मोहम्मद



की जो कि पिछले 15 साल से लगातार झीलों को साफ रखने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस नेक काम की शुरुआत अकेले ही की थी परन्तु अब उनके साथ करीब 10 लोग और जुड़ चुके हैं। हाजी सरदार बताते हैं कि वर्ष 2005 में मेवाड़ क्षेत्र में जमकर बारिश हुई थी जिसने उदयपुर की खूबसूरती में चार चाँद लगा दिए थे, पर इस खूबसूरती में कुछ दाग था तो वह था झीलों में पसरी हुई गंदगी। वे बताते हैं कि उनका घर भी झील के किनारे ही है। जब उन्होंने इस गंदगी पर ध्यान दिया तो उसी पल झीलों को साफ करने का निर्णय ले लिया।

इस बारे में उन्होंने अपने मित्र श्री जमनालाल दशोरा से भी बातचीत की और उन्हें झीलों की गंदगी व इसके दुष्प्रभावों से अवगत भी कराया। उन्होंने इनकी सहायता की और फिर शुरू हुई झील साफ करने की मुहिम।

अधिक संसाधनों के अभाव में इन्होंने ट्यूब से ही 10 नाव बनाई और जलकुम्भी निकालने का काम शुरू किया। इतनी सारी और बड़ी झीलों को किसी एक या दो व्यक्ति के लिए साफ करना असंभव था इसलिए इन्होंने एक मंच की स्थापना की जहाँ कोई भी व्यक्ति आ कर झीलों की सफाई के कार्य में श्रमदान दे सकता है। इस मंच का नाम 'झील हितैषी नागरिक मंच' रखा गया। इसमें पहले युवा शामिल नहीं हुए और शुरुआती दिनों में अधिकतर वृद्ध

लोगों ने ही श्रमदान दिया जो इस मुहिम का एक और प्रेरणादायी पहलू है। यहाँ अब धीरे धीरे युवा वर्ग का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है।

अब इनके पास ट्यूब की नाव नहीं बल्कि आधुनिक नाव है जो इन्हें 'भारत विकास परिषद उदय' ने भेंट की है। इनके झील हितैषी नागरिक मंच में किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क या दान हेतु अनिवार्यता नहीं है बल्कि दान के विषय पर हाजी सरदार मोहम्मद बताते हैं कि वे दान तो किसी से लेते ही नहीं हैं, वे लोगों से भी यही कहते हैं कि यदि आप वाकई मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो केवल श्रमदान दीजिए। इनका

मंच प्रत्येक रविवार झीलों की सफाई करने का कार्य करता है।

आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जल संरक्षण के लिए अपने जल निकायों की देखभाल करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण केवल वर्षा के जल को ही इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उन जल निकायों को साफ रखना भी है जो पहले से हमारे आसपास मौजूद हैं। सरदार हाजी मोहम्मद भी लोगों के लिए यह सन्देश देते हैं कि सभी समुदाय के लोग अपने देश के जलाशयों जैसे तालाब, नदी, झरने और बावड़ियां आदि को सुरक्षित और स्वच्छ रखने में अपना सामूहिक योगदान दें और देश को जल समृद्ध बनाएं। हमें आशा है कि आप हाजी सरदार मोहम्मद जी से अवश्य प्रेरणा लेंगे और अपने आसपास के जल निकायों की देखभाल करेंगे व उन्हें स्वच्छ रखेंगे।

पानम बांध

पानम बांध पानम नदी पर बना है। पानम नदी माही अथवा मही नदी की एक सहायक नदी है। यह बांध संतराम पुर तहसील, पंचमहल जिला, गुजरात में स्थित है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1999 में किया गया था। यह एक मिट्टी और चिनाई प्रकार का बांध है। यह बांध सिंचाई, जल आपूर्ति, मत्स्यपालन और बाढ़ नियंत्रण के लिए है। इस बांध से गोधरा सिटी को 10.64 एम एल डी जल की प्राप्ति होती है।

नींव के निम्नतम बिंदु से ऊपर बांध की अधिकतम ऊंचाई 56.36 मी है। इस बांध के शीर्ष की लंबाई 269.45 मी है। जलाशय में सकल भंडारण क्षमता 737.60 Mm³ है। इस बांध का जलग्रहण क्षेत्र 2312 वर्ग किमी (km²) है। इसमें कुल खेती योग्य कमांड क्षेत्र 36,405 हेक्टेयर (ha) है। इसमें 182.27 m शीर्ष-लंबाई का ओगी (ogee) प्रकार का स्पिलवे है जिसमें 14.93 m x 11.28 m साइज़ के 10 रेडियल गेट्स लगे हैं। पानम बांध की स्पिलवे क्षमता 10075 (m³/s) है।



PM Inaugurates 6 Sewage Infrastructure Projects in Uttarakhand under Namami Gange



Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated 6 sewage infrastructure projects in Uttarakhand under the Namami Gange Mission on September 29, 2020 through video conference. The PM also inaugurated the Ganga Avalokan Museum, a first-of-its-kind on River Ganga at Haridwar. Besides releasing the new logo for the Jal Jeevan Mission, he also unveiled the 'Margadarshika for Gram Panchayats and Paani Samitis under Jal Jeevan Mission' (Guidelines for the Village Panchayats and Water Committees) during the event. Smt. Rani Baby Maurya, Governor, Uttarakhand, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Jal Shakti Minister, Shri Trivendra Singh Rawat, Chief Minister of Uttarakhand and Shri Rattan Lal Kataria, MoS, Jal Shakti were also present on the occasion.

The PM also released a book "Rowing Down the Ganges" which, he said, explains in detail how Ganga stands as a glowing symbol of our culture, faith and heritage. Shri Modi highlighted the importance of keeping the River Ganga clean as it plays a significant role in sustaining the lives of about 50 percent of the country's population from its origin in Uttarakhand till West Bengal.

He apprised the audience of the four-pronged strategy adopted to achieve the objective that includes laying a network of Sewage Treatment Plants (STPs) keeping in mind the demands for the next 10-15 years, making around hundred big towns/cities and five thousand villages along the River Ganga Open Defecation Free (ODF) and making an all-out effort to stop the pollution in the tributaries of River Ganga.

Shri Modi highlighted that under Namami Gange, projects worth more than Rs 30,000 crores are either in progress or have been completed. He pointed out that due to these projects the sewage treatment capacity of Uttarakhand has increased 4 times in the last 6 years. With the completion of these projects, 153 MLD new sewerage treatment capacity has been created in Uttarakhand and 45 MLD STP capacity has been upgraded.

The PM listed the efforts taken to close more than 130 drains in Uttarakhand from flowing into River Ganga. He referred

specially to the Chandreshwar Nagar drain in Rishikesh which had become an eyesore.

"Had the old ways been adopted the situation would not have improved. But we have moved forward with a new thinking and new approach. We have not limited the Namami Gange mission to simply the cleanliness of the Ganga, but also made it the largest and

most comprehensive river conservation program in the country," the PM said.

Prime Minister said that the change was experienced by the pilgrims at Prayagraj Kumbh. Similarly, the visitors to Haridwar Kumbh would also experience the clean and pure River Ganga in Uttarakhand. Shri Narendra Modi referred to the beautification of the hundreds of ghats and the development of a modern riverfront at Haridwar. He said Ganga Avalokan Museum would be a special attraction to pilgrims and it would further enhance the understanding of the heritage associated with Ganga.

The PM said that apart from the cleanliness of the Ganges, the Namami Gange is focusing on the development of the economy and environment of the entire Gangetic belt. He said the Government has made comprehensive plans to promote Organic and Ayurvedic farming. Mentioning about the Project Dolphin which he announced from the ramparts of the Red Fort on August 15, 2020, the PM said that Namami Gange would strengthen the Mission to conserve Ganga Dolphins.

Shri Gajendra Singh Shekhawat emphasized on the importance of public participation in Ganga Rejuvenation and informed that several steps have been taken to connect with people and develop trained community level volunteers such as Ganga Praharis. He noted that first STP under Hybrid Annuity Mode (HAM) has been completed in Haridwar with the inauguration of 68 MLD STP at Jagjeetpur. He emphasized on the performance-oriented approach in sewerage projects through innovations like HAM and One City One Operator.

Inaugurated Projects

- 68 MLD STP at Jagjeetpur in Haridwar
- 26 MLD STP at Lakkadghat in Rishikesh
- 7.5 MLD STP at Chandreshwar Nagar
- 5 MLD STP at Chorpani in Muni ki Reti
- 1.01 MLD in Badrinath.
- Upgradation of 27 MLD Jagjeetpur and 18 MLD Sarai STPs



PM Inaugurates 2 STPs under Namami Gange in Patna, Bihar, Lays Foundation Stone for Muzaffarpur River Front

Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated two Sewerage Treatment Plants in Patna – 43 MLD in Beur and 37 MLD in Karmalichak – on September 15, 2020 under Namami Gange project. These two projects were started in October 2017 and are part of total 11 sewerage projects under Namami Gange Mission for the creation of adequate sewerage treatment capacity in Patna city. The work of 60 MLD Saidpur STP is also nearing completion. On this occasion, PM also laid the foundation stone for Muzaffarpur River Front Development scheme under which three ghats (East Akhara ghat, Ladder ghat and Chandwara ghat) of Muzaffarpur city will be developed. These river fronts will have facilities like changing rooms, pathways, watch towers, information kiosks, toilets, etc. Attractive signage, security system and adequate lighting will also be major features of these ghats. In addition to this, the PM also launched water supply project in Siwan Municipal Council and Chhapra Municipal Corporation under AMRUT scheme. Under these two schemes, local citizens will get clean drinking water round-the-clock. Shri Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister for Jal Shakti, Shri Ravi Shankar Prasad, Union Law and Justice Minister also participated in the program.

Addressing the audience, Prime Minister Shri Narendra Modi said: “Bihar has a major contribution in nation-building. Lakhs of engineers from Bihar are taking the development work of the country to new heights. The land of Bihar has always been synonymous with invention and innovation.” Shri Modi added that now basic amenities like drinking water and sewer are continuously improving in the cities of Bihar due to the joint efforts of the Center and State Government. He announced that the villages along River Ganga will be made Ganga Villages and dirty water flowing into the river will be stopped.



Talking about the projects, he said: “Today, Beur and Karmalichak STPs have been inaugurated, which will benefit the people of this region. In the coming days, Muzaffarpur River Front will also develop on the lines of Patna River Front.” PM said that under the Namami Gange, the work of construction of more than 180 ghats has been taken up across the country including Bihar, of which 130 have already been completed. He said that

recently the government also announced Project Dolphin for the conservation of the Ganges Dolphin. The entire extension of Ganga from Patna to Bhagalpur is the abode of Dolphin. Therefore, Bihar will not only benefit from Project Dolphin but will also boost tourism along with biodiversity in River Ganga.

Shri Nitish Kumar said during the event: “Ensuring that people get clean drinking water is a big task. From my own experience, I can say that getting clean drinking water involves a lot of struggle in some places and it is our responsibility to keep the water of River Ganga clean. The completion of Namami Gange sewerage projects will play a very important role and we are trying to complete all the projects soon.”

So far, 54 projects have been sanctioned for sewerage infrastructure, ghats and crematoria development, river front Development, afforestation, bio-remediation, rural sanitation and river surface cleaning in Bihar at a total cost of Rs. 6245 crore which are at different stages of implementation. It is important to note that the Patna River Front which was completed under Namami Gange Programme has already received many national and international Awards including 2A Asia Architecture Award in 2016, 2A Award Exhibition in Vienna in 2017 and Pune Design Biennale in 2017.



Namami Gange



Sh. Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister for Jal Shakti chaired the 6th meeting of the Empowered Task Force for Ganga Rejuvenation on September 25, 2020. The creation of Ganga cells in major union ministries focusing on Ganga Rejuvenation was among the issues discussed in the meeting. Sh. Shekhawat also released a booklet 'River Basin Management Plans for Medium and Minor Rivers', which provides technical insight into the small river rejuvenation efforts of various districts.



Sh. U.P. Singh, Secretary, Ministry of Jal Shakti chaired the 6th meeting of Central Monitoring Committee on September 30, 2020 for NGT Order on sewage infrastructures in various states.



NMCG in cooperation with the Indo-German 'Support to Ganga Rejuvenation' project (GIZ-SGR) & the India-EU Water Partnership (IEWP) has initiated a process to develop a policy on Treated Wastewater reuse. A meeting in this regard was organised on September 14, 2020 and chaired by Sh. U.P. Singh, Secretary, Ministry of Jal Shakti.



Sh. Rajiv Ranjan Mishra, Director General, National Mission for Clean Ganga (NMCG) delivered the closing remarks at the India-UK Water Partnership Forum and spoke about the progress of Namami Gange Programme and the way ahead.



A training programme was organised at Haidarpur wetland by Muzaffarnagar Forest Division & the Turtle Survival Alliance on October 1, 2020 with the support of National Mission for Clean Ganga (NMCG) focussing upon turtle diversity, habitat identification and reporting of turtles using Kurma App.



Sh. Rajiv Ranjan Mishra, DG, NMCG chaired the 4th NMCG-WII Project Monitoring Committee meeting, which saw participation from Dr. Dhananjai Mohan, Director-WII, Sh. Basanta Kumar Das, Director, CIFRI and Sh. Anil Joshi, Padma Bhushan a noted environmentalist.



Sh. Rajiv Ranjan Mishra, DG, NMCG chaired a meeting on World Bank aided National River Ganga basic project.



Namami Gange



As part of Ministry of Jal Shakti's 'Catch the Rain' campaign, the Wildlife Institute of India - NMCG training team of Ganga Biodiversity Conservation Phase II and local people of Chamoli village organised cleaning of artificial ponds and trenches on hilltops and removal of bushes, stone and mud in and around Village Matai, in Chamoli district of Uttarakhand on September 7, 2020. The objective of the programme was to sensitize and promote the revival of the traditional practices of Chal and Khal for storage of rainwater and to conserve water as per the geographic conditions. A total of 19 village members participated in the activity along with active support of the village Pradhan Shri Prabhat Purohit. An awareness activity involving local women and youth at village Bajhet in Dehradun, Uttarakhand was also organised on September 6, 2020 with the involvement of village Pradhan Smt. Arti Khanna and support from local youth Shri Jaydeep Khanna and Shri Gaurav Suyal.

On the occasion of World River's Day, celebrated on last Sunday of September, Namami Gange mission launched a series of exemplary work done by districts on rejuvenation of small water bodies. This year's World River's Day theme was "Day of Action for Rivers". Six districts presented case studies on smaller river rejuvenation in this first edition of small river rejuvenation series by Namami Gange. Shri Mangesh Ghildiya, DM, Tehri Garhwal, Uttarakhand shared that nine micro watersheds have been surveyed for treatment to rejuvenate Heval river, an important tributary of Ganga. Shri Manvendra Singh, DM, Farrukhabad, UP and Shri Chandra Prakash Singh, DM, Kasganj, UP presented the extra ordinary work done to revive Budhi Ganga which flows from both the districts. Also, Kuthla lake between Ganga and Ram Ganga is going to be developed as an ecological park. Shri Umesh Mishra, DM, Amroha, UP spoke about the actions taken to make river flow area of Ban River completely free of encroachment. In Mirzapur, 24 km long Karanavati river was rejuvenated mainly by massive plantation drive along the river as informed by Shri Sushil Kumar Patel, District Magistrate. A presentation on rejuvenation of Narayani River was made by DM, Vaishali, Bihar. A short-film on the plantation of Rudraksh saplings by HCL was shown at the event. HCL has planted 3500 saplings of Rudraksh this year and is committed to 3000 more next year. They will also plant 1000 saplings of other associated species. Shri Rajiv Ranjan Mishra, Director General, NMCG said: "If we see the map of all smaller rivers, it looks like a network of arteries and veins. Hence, for the overall health of ecology, it is extremely important to revive smaller rivers." He also added that rivers are not only water but a complete system which includes biodiversity, sediments and spiritual and cultural aspects.



A virtual meeting of the Monitoring Committee to review the project on 'GIS-based Mapping of Microbial Diversity across the Ganga for Ecosystem Services' was organised on September 8, 2020.



The beautiful wall mural of the journey of Ganga, made by Shri Rajesh Chandra and his team mates, has become new sepfie spot for tourists in Haridwar.



Shri Rajiv Ranjan Mishra, DG, NMCG felicitated the schools with maximum participation in Ganga Quest 2020 on September 3, 2020.

‘Catch The Rain’

In the month of September, four editions of weekly virtual series with District Magistrates/District Collectors/Commissioners as part of 'Catch the Rain' campaign were organised by National Water Mission in association with APAC Digital News Network. The series was initiated in August with an aim to learn from the varied experiences of district administrations across the country. This month, 12 District Magistrates/Municipal Commissioners/CDOs, one official of central railways, one official of MGNREGA, Kerala and two Civil Society members participated in the series

Ms. Hari Chandana Dasari, DM, Narayanpet, Telangana

Narayanpet, a border district between Telangana and Karnataka, has a cultural and religious heritage of step wells coming from the Chola Dynasty. The region is mostly rain-fed and in lean seasons depends on storage in water bodies. In the past 5 months, the efforts of district administration in the direction of rejuvenation and preservation of traditional water bodies have been phenomenal as over 200 of them have been revived. Besides, the development of almost 3000 farm ponds, formation of fish farmers' cooperative societies and construction of about 76 fish ponds have not only improved the water situation in the district, it also generated employment opportunities for the migrants due to lockdown. At the helm of these efforts is the district DM Ms. Hari Chandana Dasari. The role and efforts of district administration has invoked immense community participation. A pilot project is being undertaken in which five step wells in the district are to be revived holistically with community-centric conservation approach.



Ms. Shalini Aggarwal, DM, Vadodara, Gujarat

Panch Jal Setu Project was started in Vadodara district in 2018 for integrated management of water. The project has five components Varsha Jal Nidhi (rain water harvesting), Jal Setu (reuse and recycle of waste water in rural areas), Nal Se Jal (integrated drinking water management), Sujlam Suflam (rejuvenation of water bodies, deepening of canals) and Surya Jal Prkalp (solar panels on water tanks). A 3-tiered special committee (district, block and village) had been formed for the convergence of various departments. Funds like District Mineral funds, CSR funds have been used innovatively. Rain water harvesting in government schools in rural areas has shown a remarkable improvement due to the efforts of the administration. The campaign was spread to nearly 1000 schools by May, 2020 resulting in each school collecting 1 lakh litres of water and making Vadodara the first district in India where all schools in rural areas have Rain Water Harvesting Structures. This was done in a decentralised way through school management committees and resulted in a Bal Andolan. In addition, Nal Se Jal campaign has resulted in 96 % tap connectivity in the district. Sujlam Suflam Jal Abhiyan has led to around 2000 works mainly in deepening of ponds, canals, check dam de-silting, and excavation of new ponds. Surya Jal Prkalp, on the other hand, aims to develop



models for solar panels on water supply structures.

Ms. Swati Bhaduria, DM, Chamoli, Uttarakhand

Chamoli District in Uttarakhand is a hub for tourism and religious pilgrimage. Over the years, Mothugad, a rain-fed river in the district, began to dry up prompting the district administration to start the work of rejuvenating Mothugad River in particular and cleaning of rivers in general under Namami Gange Project. These efforts have yielded tremendous results- 16 Sewage Treatment Plants have been set up and groundwater pollution from agriculture has been controlled. Dewal block has been declared chemical-free. The level of social awareness was such that local community came up with a song in their local Gadwali language which was sung at every rally, drive, meeting associated with Mothugad, becoming the Mothugad Anthem. The work benefited 80,000 people directly and indirectly. Also, per family per year income has now increased by Rs. 40,000/- due to additional activities like apple farming.



Sh. B.N. Pani, Municipal Commissioner, Surat, Gujarat

Infrastructurally a strong city, Surat is one of the most industrialized towns in India. The growing population in the city (93% dwellers being migrants) made it necessary to manage the available water resources, especially River Tapi which is the lifeline of the city. Consequently, Tapi Rejuvenation Project was initiated as part of which water hyacinth was removed and as many as 44 drains flowing into the river were plugged. Setting an example in profiting from the reuse of water, the Surat Municipal Corporation earns about Rs. 140 crore from the sale of water of tertiary treatment plant to industries. The administration is planning to come up with three more such plants. There has been a phenomenal rise in rainwater harvesting structures in the city from 2013-14 to 2018-19. The city also maintains its 27 water bodies to develop a river-people connect. These water bodies are also connected with storm water network to ensure maximum rainwater storage and minimize flooding. One of the unique concepts in Surat city is the establishment of Water Plazas (artificial ponds) on 'social infrastructural land' which are used for idol immersions during rainy seasons. In non-rainy seasons, the Water Plazas are used for recreational activities. The Surat administration has also proposed a Barrage project wherein it plans to create a freshwater storage reservoir of 19.172 MCM that will help prevent salinity in riverbed, recharge groundwater and reduce soil erosion and flooding. It is expected to benefit a population of about 20 lakh.



“One of the purposes of dialogues is to learn from others and one of the outcomes of learning is that we respect our traditions.”

- Sh. U. P. Sinha

Sh. Piyush Singhla, Deputy Commissioner, Udhampur, Jammu and Kashmir

Udhampur district is largely a rural area. Paradoxically, despite being abundant in traditional water bodies, the district faced water scarcity, primarily due to irrational usage of available water resources. In view of this problem, a project called 'Jeevika' was launched in the district which massively focused on educating the farmers on rational use of water. Under the theme – 'Jal Sarankshan, Jeevan Parivartan', water storage structures (plastic sheet ponds) were created to store run-offs and systems like drip irrigation were promoted amongst the farmers through visits to create an integrated farming system. Crop diversification was observed and farmers were nudged to move from traditional crops like wheat/maize to vegetable production which resulted in stark improvement in their livelihood and 8-10 times increase in the income. In addition to this, pollution abatement works for River Devika, flowing through the Udhampur town, are being taken up including creation of 130 km sewer lines and 3 Sewage Treatment Plants (STPs). Also, as many as 650 water bodies have been rejuvenated as part of the water conservation work and more are being identified.



Ms. Pamela Satpathy, Commissioner, Greater Warangal, Telangana

...es of these
...n from each
...important
...we must
...nal water bodies.”

...gh, Secretary, Ministry of Jal Shakti



Acknowledging the unplanned development of the city which once used to be the capital city of Kakatiya, Ms. Pamela Satpathy apprised the audience about the unprecedented urban flash floods that hit the region in August this year completely flooding 30 wards in the area so much so that 20 were



absolutely cut off. One of the lessons from the floods was 'If We Don't Catch the Rain, Rain will Catch us Unawares'. The administration decided to act and some of the problems were found to be encroachment of water bodies, low scope of water percolation due to concretisation, lack of watershed management and transformation of old water bodies into dump yards. The water tables were found to have gone to 9.05 meter in 2019 from 7.05 meter in 2017. Consequently, focus was shifted to rainwater harvesting and about 20 government buildings were taken up as pilot. Besides, surface run-off harvesting was undertaken at about 50 parks with area of 150 acres. A total of 904 buildings (private and government) now have rainwater harvesting structures. Some of the other measures taken for effective water management include air valves with in-situ soak pits, staggered concrete pathways/paver blocks etc. Besides, at least 30 step wells have also been identified and the administration is trying to give them a facelift.

Ms. G. Srijana, Commissioner, Greater Vishakhapatnam, Andhra Pradesh

Greater Vishakhapatnam is an area which has no source of water and the administration draws its water from Pollavaram which is 160 km far. Ms. Srijana said that 'Catch the Rain', reuse of water and desalination is going to be crucial for the future of this region. She informed that the administration is in the process of collecting 120 MLD of water after tertiary treatment and earn revenue by selling it to industries. She referred to the success of Surat model which can be emulated by reorienting the thinking on matters of urgent importance with respect to water.



Sh. G. Sreekanth, DM, Latur, Maharashtra

Latur rose to global headlines when it received water through Railways in 2016. The DM of Latur, Shri G Sreekanth decided to improve the water scenario of the entire district. 'Gal Mukh Dharan' and 'Gal Mukh Shivar' were undertaken aimed at removing silt (gal) from major, minor dams, ponds, watersheds etc. Local people came together to form a group Jal Yukt Latur and contributed voluntarily. 'Nadi Parikrama Muhim' was another major effort. Paani Foundation, an NGO, now organises a Water Cup, incentivising people to reuse, recycle and reutilise water. Magic pits were constructed for storage of water. Rooftop Rain Water harvesting has been undertaken on mission mode in all government offices. Miyawaki plantation has been done at the Collector office under 'Atal Anand Van'.



Sh. Sushil Kumar Patel, DM, Mirzapur, U.P.

The situation in Mirzapur district came to a position when water tankers had to be called-in to meet the water demands of the people. The district administration swung into action in 2019 and, firstly, work on rejuvenation of River Karnavati was started. Apart from deepening of the river, pits were dug on both sides for plantation. These works were carried out through Shram Daan. In addition to this, 'Save the Ponds' campaign was run parallelly for rainwater harvesting and groundwater recharge. To rejuvenate about 126 ponds in the district, each pond was allocated to an official tasked to motivate the people to work for its rejuvenation. Subsequently, Jal Kumbhis were removed from all ponds and the results were such that the ground water level increased by around 1.42 metres since 2017-18. Agricultural productivity bettered and employment was provided to migrant labourers under MNREGA.



Sh. Shashi Ranjan, DC, Khunti, Jharkhand

Famous for its Bori Bandh initiative for water conservation, this model in Khunti district is worth emulating in water scarce villages in India. Located on a Chota Nagpur plateau, Khunti district gets rainfall of about 1200 mm every year, however, the villagers faced water problems during non-rainy season due to ineffective management of water. To address this issue, a unique initiative of Bori Bundh was started by DC,



Khunti after spreading awareness through Gram Sabhas in the district. Munda tribe, major inhabitants in the region, were sensitized in their tribal language with the help of NGOs. Subsequently, the local population got involved in the work and gave first half of their day in constructing one Bori Bundh (mini check dam) in about 3-4 days. Each Bori Bundh now irrigates about 10-15 acres of land, benefitting the farmers in all aspects of their life. Sh. Ranjan informed that so far 25 Panchayats have been covered so far. The district now has become self-sufficient for its water needs and mango plantation is being done in about 2500 acres of land. Besides, water table has increased and ahars and wells are recharged round-the-year.

Sh. Vamsi Andra, DM, Jhansi, Uttar Pradesh

Bundelkhand, being the water-deficit region, is prone to water scarcity making effective management of water resources a necessity. In view of this, 'One Village One Pond' initiative was started in March 2020 to address the water problem of Jhansi district. Sh. Vamsi Andra said that the concept is old but they stressed on the proper execution of the project. The initiative looked to dig up at least one pond in every village through MGNREGA. This fulfilled the dual responsibility of employment generation and creation of social assets. He informed that pond work in 405 Gram Panchayats has been completed out of 496 and the rest will be done by December 2020.



Sh. Alok Yadav, CDO, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

Muzaffarnagar being an industrial town faces acute problem of river pollution. In view of this, an initiative to rejuvenate River Kali was taken up by the district administration not only to arrest pollution in the river but also to increase water flow by carrying out plantation drives along its banks. About 70 km of 150 km long Kali River falls in Muzaffarnagar. The administration identified urban sewage pollution, industrial pollution and agricultural run-offs as the major problems. To begin with, the administration carried out peripheral bunding at the river bank to recharge groundwater and re-establish the river-people connect. Thereafter, the task of rejuvenation of water bodies and ponds was taken up as per which a model pond was renovated in every village on the river's banks. More than one lakh saplings were planted in a massive drive. Organic farming was also promoted on agricultural land to nudge farmers to move from water-intensive sugarcane production. Other works included construction of soak pits, nadeps, rainwater harvesting, community toilets, operation Kayakalp for schools, cleaning of village drains, plastic collection centers, IEC campaigns etc. A strict drive, with zero tolerance, was conducted to arrest industrial pollution as a result of which industrial pollution has come down considerably.



Sh. Pratham Aggarwal, Indian Railways

Shri Pratham Agarwal, Executive Engineer, Ahmednagar, Indian Railways played a crucial role in construction of trenches in villages that fall under



Ongole sub-division of railways spanning area between Karavadi Railway Station to Sri Venkateshwarpalem Railway Station (89 km) in Andhra Pradesh. The work was done along with the railway track in 4 mandals of Prakasam district namely as part of the water conservation activities conducted under the 'Convergence Scheme of MGNREGS with Railways'. The work resulted in improvement of groundwater levels in the area.

Dr. Divya S Iyer, MD, MGNREGA, Kerala

Dr. Divya informed the gathering about the water conservation initiatives taken up under MGNREGA in Kerala that includes contour bunds, contour trenches, gully plugging, gabion structures, recharge of water bodies, farm ponds, stone bunds, earthen bunds, rainwater harvesting pits etc. She said that in the past 2-3 years, 1965 works of gully plugging, 13277 of brushwood check dams, recharge of over 40000 wells, 22139 works of canal cleaning/side protection, renovation of over 24000 traditional water bodies have been completed under MGNREGA. She also talked about the river reclamation (Kuttamperoor River) and river re-linking (Meenachilar-Meenthalayar-Kodoor) projects being taken up under MGNREGA. Ms. Divya also informed the audience about the unique intervention – Coir Geo Textiles – for natural resource management.



Civil Society Members

Sh. Ranveer Tanwar

Ramveer Tanwar, a 26-year-old mechanical engineer from Dadha village in Greater Noida took upon himself the responsibility to revive the drying water bodies. Belonging to a farmer family and having seen their hardships, he set out on a campaign to motivate people to conserve water. Leaving a job with a multinational company, he started a campaign 'Jal Chaupal' along with a group of friends to spread awareness about depleting groundwater level and motivate people to limit their water usage. He also ran a unique campaign 'SelfieWithPond' to connect youngsters and spread awareness about the vanishing traditional water bodies. Today, 250 people directly and 1 lakh people indirectly are connected with his 'Boond Boond Se Pani' motto. He featured in the Water Heroes section of Jal Charcha's July 2019 issue.



Ms. Kalpana Ramesh

An architect by profession, Ms. Kalpana Ramesh started 'Blue Hyderabad' campaign to spread awareness about water conservation in general and rejuvenation of traditional water bodies in particular. Through the motto 'Be Your Own Water Hero', she urged the people to make sustainable homes with 'Reduce Wastage' mantra at the helm by harvesting rainwater and appropriately using recycled grey water. She stressed on the importance of involving women and children in campaigns for water conservation. She featured in the Water Heroes section of August 2020 issue of Jal Charcha.



जानवरों को जल की आवश्यकता क्यों है?

पक्षी जल कैसे पीते हैं?

अधिकतर पक्षी चोंच से खींचकर जल नहीं पी सकते। इस कारण, वे चोंच में जल भरने के बाद चोंच को ऊपर करके जल पेट में ढकेलते हैं। किंतु, कबूतर ऐसा पक्षी है जो चोंच को जल में डुबोकर उसे शरीर के भीतर खींचता है।

कुछ पक्षी उड़ते हुए चोंच को जल में डुबोकर भी पानी पीते हैं।

अपनी शारीरिक क्रियाएं सुचारु रूप से चलाने के लिए पक्षियों को जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पक्षियों में स्वेदग्रंथी नहीं होती हैं, इसलिए जानवरों की तुलना में पक्षियों को कम जल चाहिए होता है। उन्हें अपने पंखों को स्वच्छ रखने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है।



शोध करें!

कहा जाता है कि चातक पक्षी सिर्फ बरसात का जल पीते हैं। क्या यह सच है?



विचार करें

क्या आपके परिसर में जानवर और पक्षियों के लिए पर्याप्त जल है? नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं?

किन शारीरिक क्रियाओं के लिए जानवरों को जल की आवश्यकता पड़ती है?

मनुष्य की तरह जानवरों को भी विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारु रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें भोजन के पाचन, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन और शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है।

इसके अलावा, उभयचर जानवरों को प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है।



शोध करें!



आपके घर में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों (जैसे: छिपकली, कॉकरोच, चूहे) को जल कहाँ से मिलता है?



आप गर्मियों में पक्षियों को जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कर सकते हैं?

अपने दोस्तों के साथ बात करें और घर या स्कूल में पक्षियों को जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।



विचार करें

गर्मियों में मधुमक्खियां नल की गीली टोटी के आसपास क्यों मंडराती हैं?



मछलियां जल कैसे पीती हैं?

- मोठे जल की मछली मुंह से जल नहीं पीती। वह अपने छल्लों के माध्यम से जल शरीर में लेती है।
- समुद्र की मछली मुंह से जल पीती है।
- उसके शरीर में परिस्थिति के अनुकूल बदलाव आने की वजह से वह समुद्र का क्षारयुक्त जल पी सकती है।



The 17th Water Talk



The 17th Water Talk, organized by National Water Mission, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti was delivered by Shri S. Vishwanath, BIOME Environmental Trust, on September 18, 2020. The topic of the Water Talk was 'Bengaluru - A Metropolis and its Water Management Challenges - State, Community and Citizens'. Shri Vishwanath had been featured in the Water Heroes section of November 2019 issue of Jal Charcha, Department's monthly magazine. Shri U.P. Singh, Secretary, DOWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti participated in the Water Talk along with other officials of the Ministry.

Shri Vishwanath shared a brief history of water supply in the city of Bengaluru, threw light on its challenges and emphasized on the importance of engaging community and individuals in solving the city's water problems. The city had the first Public Water Supply Board in the country and has universal metering

of all water sources, including tube-wells. Some of the solutions offered by Shri Vishwanath included Integrated Urban Water Management, creating bylaws for rainwater harvesting, mandated recharging of groundwater, wastewater recycling and setting up water metering in every house/apartment.

He repeatedly stressed on the fact that community participation is central to successfully carry out works like recharging of wells, revival of lakes, recycling of wastewater etc. He also stressed on the importance of water literacy and the role of people, welfare associations, and companies as a watchdog holding the state responsible for proper water management. He said that Integrated Water Management may be understood as an ecosystem and requires constant "nudging" through knowledge, legal and economic means rather than physical plans alone. He added that the need is for a systems design thinking institution and not merely a 'water supply' institution.

Shri Vishwanath Srikantaiah is a water activist and urban planner. He has carried out successful campaigns at the household level and some with large community participation to conserve water in Bengaluru. Working in collaboration with local communities, Shri Srikantaiah has recharged 1 lakh wells and made 10,000 wells functional in Bengaluru. He has designed several rooftop water harvesting structures in the state of Karnataka for households and industries. Along with the Biome Environmental Trust, Shri Srikantaiah launched the project 'digging a million wells' in Bengaluru with the traditional well diggers. He is also an active member of the Rainwater Club, which has been spreading information about rainwater harvesting in the city since 1995.

जल शक्ति मंत्रालय

से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए

देखें:

जल शक्ति मंत्रालय का फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज



mowrrdgr



MoJSDoWRRDGR



ministry_of_jal_shakti

PEOPLE'S INITIATIVE



Small interventions to catch and conserve rains can do wonders to the rural economy. And this picture of a village in Pali district of Rajasthan is a living example. The lush green fields in the picture are the result of two anicuts built in this village, named Relmagra under Mukhyamantri Jalswavlamban Abhiyan. The farmers in the village are now able to sell vegetables worth Rs 3 lakhs and milk worth Rs 2 lakhs on a daily basis.



Team Green Yatra is working to bring back lost ponds in association with the HCL Foundation. Recently, the team rejuvenated the Chauganpur Pond in Greater Noida and brought it back to life.



Sh. Ramsingh Sapori initiated Bamboo plantation near Choonchali Jahaj Ghat, Noonmati, Assam with an aim to make the Char area and the bank of Brahmaputra river green.

क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाके में एक सरल, सामान्य व अत्यंत मृदु भाषी व्यक्ति ऐसा भी है जिसने किसी भी पब्लिसिटी को ना अपनाते हुए अपने इलाके में आज तक 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं। "श्री दरीपल्ली रामय्या" वह व्यक्ति हैं जिन्होंने तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले की एक कॉलोनी के 4 किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर पेड़ लगाए हैं। वह भी खुद, अकेले ही अपनी साईकिल से पौधे ले जाकर। उन्होंने बेल, पीपल, रक्त कॅंगडन, कदंब, नीम, चंदन आदि के पेड़ लगाए हैं। साथ में पेड़ के बड़े होने तक देखभाल भी की। उनका जीवन हमेशा से ही सादगी भरा रहा है। रामय्या जी की इस निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा तो कई पुरस्कार दिए ही गए हैं, साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।



NEWS IN BRIEF



Sh. G. C. Pati, Chairman CGWB chaired a meeting on “Committee to Prepare a Draft Policy Encompassing all Issues Pertaining to Uranium Contamination and its Remediation in the Country” on September 22, 2020 through a virtual conference. The meeting was attended by the members from various central ministries/ departments of central and state governments.



The Online Tier-II training programme on “Sustainable Development & Management of GW Resources” was organized by CGWB, NWR, Chandigarh for ground water professionals and sub-professionals at the state level. A total of 40 trainees participated in the training programme which includes students/research scholars, ground water professionals, central & state govt. officials, NGO'S etc. on September 18, 2020



Regional Director, SWR, CGWB and other officers of CGWB attended the 1st meeting of State Level Committee for re-estimation of GW Resources, under the chairmanship of Sh. Sanjay Gihar (IAS), Secretary, Water Resources, Govt of Goa on September 15, 2020.



Remote Sensing Dte, EMO, Central Water Commission has completed the sedimentation assessment study of Watrak Reservoir in Gujarat using the Satellite Remote Sensing (SRS) Technique. The Watrak Reservoir is located on river Watrak in the Sabarkantha district of the North-Eastern region of Gujarat. Watrak River is one of the important rivers of Gujarat with a total Catchment area of 1113.7 sq. km. The Watrak river has its origin in Aravali hills in southern Rajasthan and flows in the South-Western direction for a distance of 178.63 km before its confluence with the river Sabarmati.



CGWB Officers attended State Level Committee Meeting chaired by Secretary, Water Resources, Govt. of Chhattisgarh on issues related to Ground Water Resource Assessment 2020 and by Special Secretary, Govt of Gujarat for the reassessment of Water Resources of Gujarat state with priority on Over Exploited blocks.



Sh. G.C.Pati, Chairman, CGWB inaugurated one-week online training course on “Technical Support to Central Sector Schemes” organised by RGI on September 21, 2020. Dr. Utpal Gogoi, Member(RGNGWTRI) also graced the occasion.

On September 16, 2020, Sh. S.K. Haldar Member of Water Planning & Projects, CWC held a review meeting regarding the status of preparation of DPR of 2nd Ravi-Beas Link. Officers from CWC design wing, field units, State of Punjab attended the meeting.

NEWS IN BRIEF



Director M&A, CWC, Jammu inspected Bardo and Akhnoor GDSQ sites on Rivers Manawartawi and Chenab respectively.



On September 15, 2020, Sh. S.K. Haldar, Member, Water Planning & Projects, CWC, conducted a video conference to review the physical and financial progress of the Shahpur Kandi Dam Project. Members of the Committee from CWC design wing, field units, and from the State of Punjab and J&K attended the meeting. Sh. Haldar asked for the expedition of work related to Power Houses on Hydel Channel (in Punjab portion), work related to Main Ravi Canal Portion of J&K, and balance work of the Dam. He also asked the officials from J&K to expedite the issue related to Land Acquisition for Main Ravi Canal.

The 18th Regional Coordination Committee (RCC) meeting of the Central India Hydrology Regional Centre (CIHRC), Bhopal of National Institute of Hydrology was held online on September 2, 2020, under the chairmanship of Dr. J.V. Tyagi, Director, NIH.



A Virtual Workshop on "Drinking Water Supply and Management" for Leh Town, UT of Ladakh was organized by the Indian Institute of Sustainable Development (IISD), New Delhi from September 10-12, 2020. Sh. G.C. Patil, Chairman, CGWB graced the occasion as the Chief Guest. A presentation on "Ground Water Occurrence, Distribution and Exploration in Leh District of Ladakh" and papers on Model Bill to regulate the Ground Water Development and Ground Water Resource Estimation in the context of UT of Ladakh were also presented by CGWB in the workshop.



Inter-Ministerial Central Team (IMCT) visited the state of Arunachal Pradesh for on the spot assessment of the situation in the wake of floods/landslide from August 31 to September 2, 2020. Sh. Abhishek Sinha, Superintending Engineer, CWC, Shillong was one of the members of the IMCT.



Inter-Ministerial Central Team (IMCT) meeting with the Hon'ble CM, Uttar Pradesh for on-the-spot assessment of the situation in the wake of floods during South-West Monsoon, 2020 in Uttar Pradesh was held on September 22, 2020.



The 28th meeting of TEC of North Koel project of Bihar & Jharkhand was held on September 25, 2020, under the chairmanship of Member, WP&P.



Sh. S.K. Haldar, Member WP&P, CWC held a Video Conference with the members of Working Group on September 4, 2020, to suggest water sharing and exchange of water between Madhya Pradesh and Rajasthan w.r.t. Parbati – Kuno– Sindh (PKS) Link and Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP). Water availability in Parbati Sub-basin at the proposed Kumbhraj dam was also discussed with both state govt officials.



The 26th Governing Council meeting of CSMRS under the chairmanship of Sh. U. P. Singh, Secretary, Ministry of Jal Shakti was held on September 11, 2020.



केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 1 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़ा एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।



The first meeting of the Committee on 'Preparation of Master Plan using state-of-the-art Technology for flood management in respect of North Bihar in Ganga Basin' was held on September 24, 2020 in Patna under the chairmanship of Shri Manjeet Singh Dhillon, Chairman, Ganga Flood Control Commission (GFCC).

Indus Waters Treaty Completes 60 Years

This month marked 60 years of existence of the Indus Waters Treaty 1960 between India and Pakistan. This Treaty was signed by Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Pakistani President General Ayub Khan on 19th September 1960 at Karachi.

The Treaty fixed and delimited the rights and obligations of both the countries on use of the waters of the Indus River system. The Indus Waters Treaty is perhaps the only agreement in the world that physically divides the river system between two nations and the only one wherein a third party, the World Bank, played a crucial role in not just brokering it but also has a procedural role during its implementation.

The Treaty gave India, the absolute rights on waters of the Eastern rivers—the Ravi, Beas, and Sutlej while allotted waters of Western rivers—the Indus, Jhelum, and Chenab, largely to Pakistan but with certain rights given to India. India is permitted to tap the considerable hydropower potential of Western rivers in its territory without any quantitative limits. India is also permitted to create storage of 3.60 million acre feet and to develop an Irrigated Cropped Area upto 13.43 lakh acres from Western rivers. The Treaty does not require India to deliver assured quantities of water to Pakistan and instead it requires India to let flow to Pakistan the water available in these rivers excluding the uses permitted to her by the Treaty.

To maintain a channel for communication and to resolve various issues about implementation of the Treaty, the Treaty provided for creation of Permanent Indus Commission, with a Commissioner from each country. The Treaty provides mechanisms for resolving disputes which have helped in peacefully resolving numerous disputes.

India is making all efforts to fully utilize its rights on Eastern and Western rivers. The construction of Shahpurkandi Dam project on Ravi river which was suspended since 2014 has been resumed after intervention of this Ministry. The Ujh Dam in Ravi basin is in advanced stage of planning and 2nd Ravi Beas link is also being planned. A number of hydropower projects on Western rivers are in various stages of planning and construction.

The Indus Waters Treaty is considered one of important water treaties of the world and is widely hailed as one of the best examples of international cooperation.



A meeting was chaired on September 15, 2020 by Shri U.P. Singh, Secretary, Ministry of Jal Shakti, on 'Master Plan for Artificial Recharge of Ground Water in India' which was attended by state representatives and officials of Central Ground Water Board.



राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की में दिनांक 7 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान परिसर में प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर राजभाषा हिंदी संबंधी पोस्टर और बैनर लगाए गए तथा सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे सप्ताह के दौरान अपना मूल कामकाज हिंदी में करें। सप्ताह के दौरान तीन प्रतियोगिताएं यथा: हिंदी काव्य-पाठ, हिंदी सुलेख तथा सामान्य हिंदी एवं राजभाषा प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। मुख्य समारोह (समापन) दिनांक 24 सितंबर, 2020 को आयोजित किया गया।



Sh. Mahendra Kumar S. Sahare, Director, Appraisal Directorate, MCO, CWC, Nagpur has participated in the inter-ministerial Central team for assessment of damages caused due to flood/rains in Maharashtra from September 11-13.

National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee organized a webinar on "Water Conservation" for Kendriya Vidyalaya schools at Roorkee on September 29, 2020.



Under India-Australia MoU Cooperation in the field of Water Resource Management, 3rd Joint Working Group (JWG) meeting was held on September 22, 2020. From the India side, Indian co-chair Ms. Debashree Mukherjee, Additional Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti welcomed the JWG whereas from Australia, co-chair Ms. Lyn O'Connell PSM, Deputy Secretary - Water, Climate Adaption, Natural Disasters and Antarctic Group, Department of Agriculture, Water and the Environment welcomed the JWG. Australian High Commission in India H.E. Barry O'Farrell AO briefed and addressed the JWG. Some of the issues discussed in the meeting included update on water engagement activities since last JWG in 2018, the status of implementation of irrigation efficiency pilot project, Brahmani Baitarni IWRM Study, MARVI Project, issues related to NWIC Strategic Operating Plan (SOP), BoM capacity development program on stream-flow forecasting, setting up of hydromet testing, calibration & certification Facility lab at CWPRS. Both sides agreed to have a sub-group for frequent interaction for the speedy implementation of the MoU.

National Institute of Hydrology (NIH) and Indian National Committee for Intergovernmental Hydrological Programme (INC-IHP) organized "Himalaya Day" on September 9, 2020. The webinar was attended by about 1100 enthusiasts from various organizations. At the outset of the webinar, a short film entitled "Save Himalaya to Save Our Future" was featured.

National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee successfully organized a five-days virtual/online training course on "Hydrological Modeling Using SWAT" from September 21-25, 2020. More than 60 participants attended this online course from various academic institutions, research institutions, and universities across the country including scientists, academicians, researchers, and engineers.

NWM held a workshop on 'Mines Water Management' on September 24, 2020 on virtual platform. Sh. G. Asok Kumar, Additional Secretary & Mission Director, NWM gave the keynote address and Sh. Satendra Singh, Joint Secretary, Ministry of Mines and Sh. Bhabani Prasad Pati addressed a session during the webinar. Expert speakers who spoke during technical sessions belonged to the organizations – Western Coalfields Ltd., IIT, NIDM, JNU and Mu Gamma Consultants Pvt. Ltd. The expert speakers discussed issues related to integrated mine water management, challenges in this sector, success stories in mine water utilization, water quality management in mining areas.



Let's Take a Pledge: We Will Save Water

मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद।
प्यासे ही तो रह जाओगे, मेरे बिना ना जी पाओगे।।

70% (3/4 part) of the Earth is containing water in the form of icebergs, ocean, seas, rivers, lakes etc. but what a tragedy that still there is water scarcity. Water scarcity is not for earth but for human beings as all the water available on Earth can't be utilised for household works, agriculture or in drinking. The fact is only 2.5% water is fresh and out of which only 1% is easily accessible.

In earlier days, there were arrangements of piau/mashak etc. for travellers but now a days water is selling in the form of mineral water bottles and we purchase it also. Such a drastic change is there but this change didn't happen at once. It was a gradual change but we realised its consequences later in the form of water scarcity.

In earlier days there was no problem of potable water as water resources like rivers were clean and sufficient amount of underground water was available but due to population explosion the demand of water has increased. Some of the key factors responsible for scarcity of potable and clean water are:

- 1) human interference in nature as factories are increasing day by day and the waste of these factories get mixed into water resources and polluting them.
- 2) Luxurious lifestyle of human being which causes use of ROs, showers for bathing, car washing etc.
- 3) Cemented roads and tiled/ marbelled floors in homes due to which rate of percolation of water is decreasing and level of underground water is also decreasing. All these factors causes a lot of wastage of water and this water cannot be reused.

Now the question is that who is responsible for this change? How can we save water? How can we increase underground water level. Seems to be such a big question, a big problem! But is it really a major problem? Yes it will remain a major problem until we human beings don't change our habits, don't become responsible citizens. Otherwise it's not such a big issue. A lot of suggestions, schemes, remedies and awareness programmes are initiated under various government organizations, ministries, NGOs etc.

But the actual problem is of implementation by the people. Our thinking is what change can I bring alone as others are not following and this is the real problem. We all have to change our thinking. Some of the efforts we all can make are:

- Making of Rainwater harvesting system in societies, offices, factories, homes etc
- Use of material for roads that enables percolation of rainwater
- Proper disposal of factory waste and proper drainage system
- Proper use of water for household works
- Growth of more water efficient crops
- Keep the tap closed while doing tooth brush, handwash, doing washing of dishes etc.

Anupama Bansal (Hindi phrase written by Sh. Ravi Shrivastava)

Vice Principal
KV No 2 Chandimandir Cantt
Panchkula



रमेश गोयल -सिरसा-हरियाणा

जलशक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में 2019 से प्रकाशित मासिक पत्रिका "जल चर्चा" जल संरक्षण व जल संग्रहण के क्षेत्र में बहुत सार्थक प्रयास है। देश भर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करने वाले जल संरक्षण कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन रही है वहीं जलशक्ति मंत्रालय की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से जल सम्बन्धित समस्याओं को उजागर करने व कम करने में "जल चर्चा" का योगदान बहुआयामी व प्रशंसनीय है।

Feedback



नीरज वानखडे- तीगांव, मध्य प्रदेश

जल शक्ति मंत्रालय लगातार जल संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। साथ ही जल चर्चा मैगज़ीन के द्वारा अपनी बात और हमारी बात लोगो तक पहुंचाते हैं और देश भर में जल संरक्षण के लिए हो रहे कार्यों को भी मासिक पत्रिका जल चर्चा में स्थान दिया जाता है। साथ ही आम जनता द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण के प्रयासों को भी पहचान दी जाती है तथा सभी के योगदान को सराहा भी जाता है। सालों बाद देश में ऐसी क्रांति आयी है, जल संकट से निजात पाने के लिए मेरे जैसे आम आदमी के संघर्ष को भी आप ने जल चर्चा पर जगह दी है।

ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (TRDC)

आज के समय में इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि गैर सरकारी संगठन पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ज़मीनी स्तर से जुड़े होने के कारण इन संगठनों की पहुँच सरकार या फिर किसी एक अकेले मनुष्य से कहीं ज्यादा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से लोगों को इस तरह के संस्थानों के बारे में पता लगा है वे अपने पर्यावरण व परिवेश से और बेहतर तरीके से परिचित हुए हैं। जल चर्चा के प्रत्येक संस्करण में हम आपको ऐसे ही गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन से परिचित कराते हैं जो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु देश के उन शहरों में से हैं जो पिछले कुछ वर्षों से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए ही यहाँ कई गैर सरकारी संगठन और लोग युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही संगठनों में से एक हैं -ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (TRDC)। यह बेंगलुरु स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। यह संगठन सभी से बच्चों, युवाओं, महिलाओं के हितों एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु कार्य कर रहा है। ये लोगों को शिक्षित करते हैं, उनकी कौशल विकास में सहायता करते हैं एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति 'सेंसाइज' करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया है और साथ ही साथ इसके प्रभाव कम करने के तरीके भी सुझाए हैं। यह संगठन पौधे, वृक्ष, वन एवं जीव जंतुओं के संवर्धन हेतु लोगों को प्रेरित करता है और लोगों के साथ मिलकर जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु कार्य करता है। संगठन का लक्ष्य रहता है कि इस प्रक्रिया में वे अधिक से अधिक युवाओं एवं किसानों को शामिल कर सकें। पिछले वर्षों में संगठन लोगों को यह समझाने में सफल रहा है कि यदि हम अपने जल निकायों का सही अनुरक्षण करें तो बाढ़ एवं सूखे की विकट समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है।

टीआरडीसी इस समस्या को 'ग्रास रूट लेवल' पर ही खत्म करने के लिए बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने का कार्य करता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण से प्रेम करने और इसके संरक्षण करने की सीख मिलेगी। इन बच्चों को रचनात्मक तरीके से शिक्षित करने के लिए ये फिल्म शो, प्रेजेंटेशन, क्विज़ एवं पज़ल्स का इस्तेमाल करते हैं।

जल संरक्षण के क्षेत्र में टीआरडीसी द्वारा उत्तर कन्नड़ में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत वे गाँवों के टैंक और झीलों के पुनर्वासन का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में पुराने समय से ही सिंचाई एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति टैंक द्वारा की जाती है परन्तु लापरवाही के कारण ये टैंक अपना असली स्वरूप खोते चले गए। इस संगठन ने लोगों के साथ मिलकर इन टैंक को पुनर्जीवित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग हर गाँव में वर्षा जल संचयन हेतु पिट बनवाए हैं। लोग अब इन साधारण से

उपायों की अहमियत समझ रहे हैं और जल संरक्षण की इस मुहिम में टीआरडीसी का साथ दे रहे हैं। वाकई इस एनजीओ द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी टीआरडीसी की पहल से प्रेरित होकर जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान अवश्य देंगे।



बेरिमुरा एच.एस स्कूल, त्रिपुरा

स्कूल वह जगह है जहाँ बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है और देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव की स्थापना होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत विद्यालयों से ही होनी चाहिए क्योंकि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए आरंभिक स्तर में व्यावहारिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आज जो पर्यावरणीय संकट इस धरा पर छाया हुआ है उसमें केवल बच्चों के रूप में ही हमें उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है और इसका कारण यही है कि ये बच्चे एक बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम हैं, केवल आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। इस उचित मार्गदर्शन का कार्य विद्यालय करते हैं। देशभर में अनेकों विद्यालय पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में शामिल हो रहे हैं तथा विद्यार्थियों को इस जनकल्याणकारी अभियान में शामिल कर रहे हैं। ऐसे ही विद्यालयों के जल संरक्षण की कहानियाँ हम आपके साथ 'जल चर्चा' के माध्यम से साझा करते हैं।

इस संस्करण में हम आपको त्रिपुरा स्थित एक विद्यालय से परिचित कराने जा रहे हैं। बेरिमुरा एच.एस विद्यालय, पश्चिमी त्रिपुरा के बमुटिया क्षेत्र में स्थित है। यह विद्यालय राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी राज्य व देश के श्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में जगह बनाए हुए है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग के स्वामित्व में है तथा इसका पूर्णतः संचालन भी शिक्षा विभाग द्वारा ही होता है। विद्यालय में अकादमिक, खेल एवं अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाकर विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल में क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और अन्य खेलों के लिए सुन्दर और अच्छी सुविधाओं वाले खेल के मैदान बनवाए गए हैं।

बस खेल ही नहीं विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं से अवगत कराने हेतु यहाँ अलग-अलग तरह की रचनात्मक गतिविधियाँ व प्रतियोगिताएँ भी समय-समय पर आयोजित कराई जाती हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष जल संरक्षण के विषय पर पेंटिंग, निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाती हैं। हाल ही में यहाँ 'सेव वॉटर एंड कंजर्व वॉटर फॉर फ्यूचर' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराई गयी। इसमें बच्चों ने जल संकट के परिणामों और प्रभावों की बात की। ये प्रतियोगिताएँ केवल बच्चों के भाव व्यक्त करने का माध्यम नहीं हैं बल्कि उन्हें गंभीर समस्याओं से अवगत कराने का भी एक माध्यम हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले कर बच्चों के भीतर इन समस्याओं से निदान पाने की भावना भी जागृत होती है और विश्व में परिवर्तन लाने का भाव आता है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी बच्चों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति जो जल का इस्तेमाल कर रहा है उसे जल का मूल्य पता होना चाहिए और ऐसी बहुमूल्य वस्तु को मुफ्त नहीं होना

चाहिए। यह भी बताया गया कि जल की बर्बादी करने और इसे दूषित करने वालों के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के जल संसाधनों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ बच्चों को जल संरक्षण के विषय पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दिए गए, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने जल के पुनरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रोजेक्ट बनाए। इन सभी प्रतियोगिताओं और गतिविधियों से यह सिद्ध होता है कि भारत के भविष्य के कर्णधार, पर्यावरण व इस पर मंडराते संकटों से भली-भाँति परिचित हैं, उन्हें केवल सही राह दिखाने की आवश्यकता है।

विद्यार्थियों को जल संरक्षण की मुहिम में शामिल करने के लिए 'वाटर सेविंग टोम्स' और 'वाटर मॉनिटर' बनाए जाते हैं, ये विद्यार्थियों में से ही चुने जाते हैं एवं इन्हें यह ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वे यदि कहीं जल बर्बाद होता देखें तो उसे रोकने के लिए उचित कदम उठाएँ या फिर शिकायत करें। ऐसी गतिविधियों से बच्चों में नेतृत्व और ज़िम्मेदारी की भावना आती है। बच्चे अपनी बोतलों के पानी को फेंकने की जगह, उस पानी को मैदान में लगे पौधों में डालते हैं। ये छोटे-छोटे कदम एक बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं जो एक दिन बड़ा परिवर्तन लाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कदमों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना ले तो शायद हम जल संकट को थोड़ा पीछे धकेल सकते हैं। हमें आशा है कि आप इन बच्चों की छोटी सी पहल से अवश्य ही प्रेरित होंगे और खुद भी जल संरक्षण की मुहिम का हिस्सा बनेंगे।





जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION



save
water

“Water Heroes – Share Your Stories 2.0”

**Win cash prize of
₹ 10,000**

Monthly 10 prizes of ₹ 10000/- each with certificate.

has now UNLOCKED!

Submit your entries.

For more details visit : www.mygov.in
www.jalshakti-dowr@gov.in

नदी की कहानी

पर्वतों से निकली, एक निर्मल सी धारा
जब बह निकली तो नदी कहलायी
टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर
हरी भरी घाटियों से फिसलकर
फलों के बागानों में खोई
वृक्षों के झुरमुट में सोई
पक्षियों के साथ चहचहाई
नीले रंग में रंग कर आई
कभी गरजी तो कभी भँवर सी घूमी
कल कल मधुर संगीत के साथ आई
खेतों को हरे रंग से रंग दिया
और अन्न का भंडार उपहार में दिया
सुंदर पुष्पों से धरती महकाई
घर घर में खुशियाँ ले आई
आसमान से धरा पर उतरी
मैदानों और रेगिस्तानों में लहराई
पर बदले में मिली जहरीली गंदगी
दूषित होकर तुम रोई
दिया मनुष्य को जीवन पर
बदले में मृत्यु है पाई
रोते रोते सागर में खोई
और उसमें मिलकर गुम हो गई
नदी की कहानी भी खत्म हो गई ।

संदीप धनोते, CSMRS

Share your suggestions & feedback at media-mowr@nic.in